भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

08.02.2023 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1129 का उत्तर

आमान परिवर्तन

1129. श्री रवि किशन:

श्री रविन्दर कुशवाहा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्यात अब भी कई रेलगाड़ियां मीटर गेज लाइन पर चल रही हैं;

(ख) यदि हां , तो ऐसे मार्गों का ब्यौरा क्या है

(ग) इन मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइन में परिवर्तित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) आमान परिवर्तन के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ड.) आमान परिवर्तन में बाधा का सामना करने वाले रेल मार्गों के नाम क्या हैं; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): जी हां। इस समय, भारतीय रेल के मीटर गेज खंड पर यात्री रेलगाड़ी सेवाएं नामत: मथुरा-वृन्दावन, मैलानी-बिछिया, बहराइच-नेपालगंज रोड, मारवाड़-मावली, मेट्टूपालयम-उदगमण्डलम, कूनूर-उदगमण्डलम, वेरावल-अमरेली, वेरावल-देलवाड़ा, देलवड़ा-जूनागढ़, जूनागढ़-अमरेली चलाई जा रही हैं।

एक आमान परियोजना संबंधी नीति को वर्ष 1992 में धरोहर लाइनों अथवा वन्यजीव सेंचुरी / नेशनल पार्कों से गुजरने वाली लाइनों को छोड़कर चुनिंदा मार्गों को बड़ी लाइन में परिवर्तन करने के लिए शुरू किया गया था।

01.04.2022 की स्थिति के अनुसार , भारतीय रेल पर 5,667 किलोमीटर लंबाई की 50,250 करोड़ रुपये लागत वाली 42 आमान परिवर्तन परियोजनाएं योजना/स्वीकृति/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं जिनमें 3,488 किलोमीटर लंबाई को चालू कर दिया गया है और मार्च , 2022 तक 19,235 करोड़ रुपये व्यय किया गया है।

किसी भी रेल परियोजना को पूरा होना विभिन्न कारकों जैसे राज्य सरकार द्वारा भूमि का शीघ्र अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृति , लागत में भागीदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा हिस्सा जमा कराना , बाधक जनपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृति , क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना स्थल के क्षेत्र की कानून एवं व्यवस्था संबंधी स्थितति, जलवायु परिस्थिततियों के कारण विशेष परियोजना स्थल के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं, जिसका अंतिम निर्धारण पूरा होने की स्थिति पर किया जाता है। इसलिए , इस स्थिगति में परियोजना के पूरा होने की निर्धारित समय -सीमा नहीं दी जा सकती है। बहरहाल , रेलवे परियोजनाओं को पूरा करने के पूरे प्रयास कर रही है।

सरकार द्वारा रेल परियोजनाओं के प्रभावी और शीघ्र कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें (i) गति शक्ति इकाई की स्थापना (ii) परियोजनाओं को वरीयता (iii) वरीयता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन का आबंटन (iv) फील्ड लेवल पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की गहन निगरानी (vi) भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव स्वीकृति और परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित अनुवर्तन करना शामिल है। इससे 2014 के बाद कमीशनिंग की दर में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है।

*****